शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 26 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 20 – 27 जून 2022 मूल्य पांच रूपए

मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के सार्वजनिक संवाद पर उठते सवाल

शिमला/शैल। इन दिनों प्रदेश में नेता सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष में

सार्वजनिक संवाद जिस स्तर तक पहुंच गया है उसे आम आदमी मर्यादाओं का

अतिक्रमण करार दे रहा है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का आपसी संवाद जब मर्यादाए लांघना शुरू कर देता है तो आम आदमी पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं रह जाता है। क्योंकि ऐसे संवाद में एक – दूसरे पर ऐसे आरोप अपरोक्ष में लगाये जाते हैं जिन पर न चाहते हुए भी आम आदमी का ध्यान चला जाता है और वह अपने ही स्तर पर अपने निज के लिये ही उनकी पड़ताल करना शुरू कर देता है। ऐसा वह इसलिये करता है कि इन नेताओं की जो तस्वीर उसने अपने दिमाग में बिठा रखी होती है उसका आकलन वह नये सिरे से कर सके। प्रदेश के इन शीर्ष नेताओं में हुये सार्वजनिक संवाद का विषय हेलीकॉप्टर का उपयोग/ दुरुपयोग बना है। यह एक सार्वजनिक सच है कि शायद मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा की माइलेज उनकी रोड यात्रा से बढ़ जाये। यह भी सच है कि प्रदेश में सड़कों की सेहत दयनीय है। इनकी मुरम्मत में किस तरह की गुणवत्ता अपनाई जा रही है उसके प्रमाण राजधानी शिमला से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में मिल जायेंगे। कैसे तारकोल मिट्टी पर ही बिछा दिया जा रहा है इसके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग और पर्यटन का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है इसलिये हेलीकॉप्टर पर सबकी नजर चली जाती है। क्योंकि अधिकारियों को यह पता होता है कि मुख्यमंत्री ने तो हवाई मार्ग से ही आना है इसलिये उन्हें सड़कों की जमीनी हकीकत का पता क्यों और कैसे लगेगा। फिर मुख्यमंत्री के गिर्द मंडराने का अवसर भी उन्हीं को मिलता है जो हरा ही हरा दिखाने में पारंगत होते हैं।

ऐसे में जमीन से जुड़े और उसके सरोकारों से बंधे लोगों का हेलीकॉप्टर के उपयोग को लेकर आपस में बातें करना तथा सवाल उठाना स्वभाविक हो जाता है। इन लोगों को यह भी जानकारी रहती है कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त और कौन लोग इस में यात्रा कर लेते हैं। बल्कि एक समय तो जन चर्चा यहां तक रही है कि कुछ लोगों ने तो नाम बदलकर हवाई यात्रा की है। शायद उनके पद के कारण अपने ही नाम से यात्रा करना उनकी निष्पक्षता को प्रभावित करता। ऐसे में हेलीकॉप्टर के उपयोग को लेकर विपक्ष का परोक्ष/अपरोक्ष में सवाल उठाना स्वभाविक हो जाता है। शायद इन सवालों की धार कुछ ज्यादा पैनी होती जा रही थी जिस पर मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंच से यह कहना पड़ गया कि यह हेलीकॉप्टर नेता प्रतिपक्ष के टब्बर का नहीं है। मुख्यमंत्री के इस कथन का जवाब नेता प्रतिपक्ष ने भी उसी शैली में देते हुये यह कह दिया कि यह हेलीकॉप्टर न उनके परिवार का है और न ही मुख्यमंत्री के परिवार का। यह प्रदेश सरकार का है और इसके हर उपयोग की जानकारी हर आदमी को जानने का अधिकार है। आरटीआई के माध्यम से यह जानकारीयां मांगी जा सकती हैं। यह जवाब देते हुये नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कह दिया कि यह हेलीकाप्टर सहेलियों के लिए भी नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष के इस जवाब से आहत होकर प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष को बिना शर्त माफी मांगने के लिये कहा है। उन्होंने सहेली शब्द को असंसदीय करार देते हुये यह भी कहा है कि उनके पास कानूनी कारवाई करने का भी विकल्प है। राकेश पठानिया ने इसी पत्रकार वार्ता में यह भी आरोप लगाया कि जब मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र सरकार में उद्योग मंत्री थे तब उनके क्षेत्र में हुये 73 करोड़ के कार्यो को लेकर भी काफी कुछ मसाला उनके खिलाफ है। पठानिया के मुताबिक इस 73 करोड़ के खर्च में भ्रष्टाचार हुआ है। जिस पर मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ मामला बनता है जो अब तक नहीं बनाया गया है। राकेश पठानिया जयराम सरकार में वन मंत्री हैं और इस सरकार का यह अंतिम वर्ष चल रहा है। आज पठानिया ने जो 73 करोड़ के खर्च में घपला होने का आरोप लगाया है यह आरोप पहली बार लगा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जयराम सरकार के संज्ञान में यह मामला पहले दिन से रहा है। लेकिन यह सरकार इस पर इसलिये चुप रही क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री सरकार के खिलाफ शायद इतने आक्रामक नहीं थे। अब जब आक्रमक हुये हैं तब उनके खिलाफ यह मामले याद आ रहे हैं या बनाये जाने की धमकी है यह जो भी हो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार इस सिद्धांत पर चलती रही है कि तुम हमें कुछ मत बोलो हम तुम्हें नहीं बोलेंगे। जयराम के मंत्री का यह ब्यान कानून की नजर में बहुत मायने रखता है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब अवश्य मांगेगी। अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि जयराम अपने ही मंत्री के इस वक्तव्य का क्या जवाब देते हैं। क्योंकि जनता को यह जानने का हक है कि सही में भ्रष्टाचार हुआ है या मंत्री सार्वजनिक रूप से डरा रहे हैं।

राकेश पठानिया ने मुकेश से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है अन्यथा कानूनी विकल्प चुनने की बात की है। लेकिन मुकेश ने अब तक माफी नहीं मांगी है तो क्या पठानिया अदालत जायेंगे? यह देखना दिलचस्प हो गया है। दूसरी ओर मुकेश के ब्यान के बाद संयोगवश प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉ. रचना गुप्ता का भी एक ट्वीट आया है। यह मुकेश के ब्यान की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। यह ट्वीट भी यथास्थिति पाठकों के सामने रखा जा रहा है। वैसे कानूनी शब्दकोष के मुताबिक सहेली शब्द असंसदीय नहीं है। विश्लेषकों के लिये मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के सार्वजनिक संवाद के दौरान डॉ. गुप्ता के ट्वीट के मायने और संदर्भ समझना एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

- क्या मुकेश अग्निहोत्री के उद्योग मंत्री काल में 73 करोड़ के खर्च में भ्रष्टाचार हुआ है?
- यदि हां तो सरकार अब तक चुप क्यों थी?
- यदि नहीं तो क्या मुकेश को डराने का प्रयास हो रहा है।
- इसी दौरान आये डॉ. रचना गुप्ता के ट्वीट के मायने क्या है।

यह है ट्वीट

केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेती में रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का किया आह्वान

शिमला/शैल। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने खेती में रासायनिक आदानों पर निर्भरता को कम करने के लिए

वैकल्पिक कृषि पद्धतियों के प्रचार और विकास की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।तोमर ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का दौरा करते हुए यह विचार व्यक्त किये। तोमर ने सोलन में एक कार्यक्रम में शामिल होना था जिसके लिए वह विश्वविद्यालय में ठहरे थे।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल के साथ चर्चा के दौरान कृषि मंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए प्राकृतिक खेती पर पाठयक्रम तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की प्रगति पर भी जानकारी ली। इस राष्ट्रीय समिति के सदस्य प्रो.चदेल ने कृषि मंत्री को समिति द्वारा किए गए कार्यो के बारे में जानकारी दी। तोमर ने सुझाव दिया कि पाठयक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित हो ताकि इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके और छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक प्राकृतिक फार्म को डिजाइन और स्थापित कर सकें। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना के बारे में भी जानकारी ली और किसानों और इस विधि के परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्राकृतिक कृषि पद्धति किसानों के लिए न केवल उनकी आजीविका को बनाए रखने के मामले में वरदान साबित हो रही है, बल्कि बाजार संचालित रासायनिक आदानों पर किसानों की निर्भरता, पानी की बचत और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर रही है।

प्रोफेसर चंदेल ने तोमर को राज्य सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों और प्रयोगों जिनसे प्राकृतिक खेती की अवधारणा को बढ़ावा और प्राकृतिक कृषि प्रथाओं पर वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा हो रहा है के बारे में भी बताया। उन्होंन तोमर को राज्य में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ बातचीत करने और उनके खेतों का दौरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश आने का अनुरोध किया।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर के नेचर पार्क में देवदार का पेड़ भी लगाया। इस अवसर पर उनके साथ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल, शिमला के सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और विश्वविद्यालय के सभी वैधानिक अधिकारी मौजूद रहे।

राजभवन शिमला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित

शिमला/शैल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन शिमला में आयुष विभाग एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम

का आयोजन किया गया। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रोफेसर डॉ.सत्य प्रकाश की अगुवाई में राजभवन के कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। राज्यपाल ने भी योग क्रियाएं कीं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योग के माध्यम से हमारी समृद्ध परम्पराएं विश्व के समक्ष उजागर हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रभावी प्रयासों से इस विधा को विश्व के समक्ष रखा और यह समझाया कि यह किसी धर्म अथवा पूजा पद्धति से सम्बद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि योग हमें शारीरिक एवं आत्मिक शांति प्रदान कर सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने कहा कि हमें योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि अगर हम अपनी विशिष्टताओं को भूला देंगे तो कभी भी विश्वगुरू नहीं बन सकते। हमें अपनी परम्पराओं को संजोए रखना चाहिए।

इससे पूर्व डॉ. सत्य प्रकाश ने राज्यपाल को अपनी पुस्तक 'हठ योग के आधार एवं प्रयोग' भेंट की। उन्होंने आयुष विभाग की एक सीडी और 'योग संहिता' भी राज्यपाल को भेंट की। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रथम न्यूज़लेटर का भी विमोचन किया। उन्होंने गैर संचारी रोगों के लिए योग प्रबन्धन विषय पर एक पुस्तिका भी जारी की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने भी सम्बोधन किया।

दिव्यांग योद्धाओं ने की राज्यपाल से भेंट

शिमला/शैल। दिव्यांग योद्धाओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। सात दिव्यांग योद्धाओं का यह दल

लखनऊ से लेह और लद्दाख से कानपुर तक का 4000 किलोमीटर का सफर 15 दिनों में हाथों से चलने वाली एडॉप्टर कार से कर रहा है। 'चलो जीतें हम' नाम से प्रारम्भ किए गए इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को भारत की गौरवशाली प्रतिभा से जोड़ना है।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने दल का उत्साहवर्द्धन करते हुए कहा कि यह उनकी अपनी जिद्द है कि वे इस अभियान पर निकले हैं और यह अन्यों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांग साथियों के मन में आत्मविश्वास बढ़ाने व देश के सार्वजनिक स्थलों का परिवेश बाधामुक्त करना इस यात्रा का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त 'एक जनपद एक उत्पाद' की धारा से दिव्यांगजनों को जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाना भी इसका उद्देश्य है ताकि उनको अपने गांव व शहर में रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। यात्रा अभियान के मुख्य संयोजक सुनील मंगल व उनके साथी सेवानिवृत स्क्वाड्रन लीडर अजय प्रताप सिंह ने इस अवसर पर राज्यपाल को अभियान की विस्तृत जानकारी दी।

अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के एशिया प्रमुख का हिमाचल दौरा

शिमला/शैल। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के एशिया प्रमुख उदया रेग्मी ने प्रदेश में अपने तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की तथा हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यो एवं गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने

राज्यपाल को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस की सहायता से की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यावसायिक तथा सामुदायिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी बल दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

राज्यपाल ने उनके सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों को और गति देने की आवश्यकता है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन के नालागढ़ में शीघ्र ही रेडक्रॉस ब्लड बैंक खोला जाना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस द्वारा उपकरण व एक ब्लड कलेक्शन वैन भेंट की जानी है, जो कि सराहनीय है। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि ऊपरी हिमाचल के लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के लिए शिमला का रूख करते हैं, इसलिए यहां पर डायलिसिस की सुविधा होना आवश्यक है।

इसके उपरान्त, उदया रेग्मी ने डॉ. साधना ठाकुर से भी भेंट की तथा हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में चर्चा की।

डॉ. साधना ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस की सराहना करते हुए कहा कि फेडरेशन द्वारा समय-समय पर हिमाचल प्रदेश रेडक्रॉस को सहायता प्रदान की जाती रही है, जिसमें कोविड-19 में संकटकाल के दौरान मास्क, स्वच्छता किट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, साबुन इत्यादि प्रदान करना प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा इस संस्था द्वारा इस वर्ष एक एडवांस लाइफ सपोर्ट वैन व एक बेसिक लाइफ सपोर्ट वैन प्रदान की गई है।

रेग्मी 22 जून को जिला रेड क्रॉस बिलासपुर की गतिविधियों का अवलोकन कर 23 जून को मण्डी जिला रेड क्रॉस का दौरा करेंगे है। वह नालागढ़ में तैयार हो रहे ब्लड बैंक का भी निरीक्षण करेंगे।

बैठक में उनके साथ हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस के सचिव संजीव कुमार, उपाध्यक्ष अस्पताल कल्याण अनुभाग मधु सूद व मानद सचिव अस्पताल कल्याण अनुभाग डॉ. किमी सूद भी उपस्थित थीं।

एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 50 छात्रों की टीम केरल रवाना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईटी) ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उत्सव को जारी रखते हुए मिशन 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत केरल के दौरे के लिए राज्य के 50 छात्रों की एक टीम को हरी झंडी दिखाई। इस दल में एचपी-यूआईटी और एचपी राज्य शिक्षा विभाग प्रत्येक से 25 चयनित छात्र शामिल हैं। पांच दिवसीय कार्यक्रम 28 जून से 2 जुलाई तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आयोजित किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ज्योति प्रकाश ने निदेशक यूआईटी प्रो. पी.एल.शर्मा, समन्वयकों और अन्य संकाय सदस्यों की उपस्थिति में टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया।

अपने उद्घाटन भाषण में प्रो. प्रकाश ने कहा कि यह हमारे छात्रों के लिए अन्य राज्यों की संस्कृति, कला और साहित्य को सीखने का एक बड़ा अवसर और अनुभव है।

इस अवसर पर बोलते हुए, यूआईटी के निदेशक, प्रो. पी.एल. शर्मा ने कहा कि विभिन्न राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे एक-दूसरे के साथ साहित्यिक खजाने को साझा करें और इस अंतर्निहित बंधन को और भी मजबूत बनाते हुए हमारी संस्कृति को समृद्ध करें। पांच दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, छात्र केरल के विभिन्न स्थानों और संस्थानों का दौरा करेंगे। छात्र 'गॉड्स ओन कंट्री को जानना' पर चर्चा में भाग लेंगे, इसके अलावा टीम हिल पैलेस संग्रहालय, कोचि मेट्रो रेल लिमिटेड, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रद्योगिकी संस्थान और क्यूसैट साइंस लैब का दौरा करेगी। छात्र मरीन ड्राइव भी करेंगे और कोचि हार्बर और कोचि बंदरगाह में ज्यू स्ट्रीट और परेड ग्राउंड का भी दौरा करेंगे।

टीम का रासा गुरुकुल, चेंदमंगलम हैंडलूम यूनिट, आरएलवी कॉलेज, लोकगीत संग्रहालय और प्रसिद्ध समुद्र तटों का दौरा करने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि एक राज्य के छात्र युग्मित राज्य के भाषाई और सांस्कृतिक पहलुओं जैसे इतिहास, संस्कृति, व्यंजन, भाषा, त्योहारों, कपड़ों को सीखेंगे। विशेष रूप से, डॉ.प्रदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर और रीतम नेगी यूआईटी के छात्रों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जबकि रोहित गुलेरिया और वर्षा सूद राज्य शिक्षा विभाग के छात्रों का संचालन करेंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए व्यापक योजना तैयार:जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग और हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की पहल, 'नशा नहीं, जिंदगी चुनो' का शुभारंभ करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए एकीकृत नशामुक्ति नीति अपनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरे जाएंगे ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार के राजस्व की बचत होगी बल्कि इससे नशीली दवाओं के खतरे से समग्र रूप से निपटने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस अवसर पर आबकारी पुलिस बल की प्रक्रिया का शुभारम्भ भी किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाना समय की मांग है तभी नशे जैसी बुराई को खत्म किया जा सकता है और युवा पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस समय में नशे के खतरे पर अंकुश लगाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग को एक कदम आगे रहने का परामर्श दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल आवश्यक है तभी नशीले पदार्थों की तस्करी की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पहल पर ही इस क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकुला में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों और अन्य उत्तरी राज्यों के अन्य प्रतिनिधियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब द्वारा एक और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 के अन्तर्गत एक विशेष नशामुक्ति हेल्पलाइन भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन का उद्देश्य मरीजों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। नशीली दवाओं के खिलाफ रणनीति मुख्य रूप से भांग और अफीम जैसे पौधों से प्राप्त कुछ मादक पदार्थों पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने इन मादक पदार्थों के उत्पादन वाले पौधों की खेती के खिलाफ और उन्मूलन के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों और इसके अवैध व्यापार में शामिल लोगों की लगभग 20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

जय राम ठाकुर ने अभिभावकों को भी सलाह दी कि वे अपने बच्चों के व्यवहार और उसमें होने वाले परिवर्तन पर निगरानी रखें और अभिभावक अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। उन्होंने शिक्षकों से स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के आस-पास चल रही गतिविधियों पर नजर रखने का भी आग्रह किया, क्योंकि नशा तस्कर इन संस्थानों को विशेष रूप से निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पुलिस योजना के तहत समय-समय पर स्कूलों और कॉलेजों के पास युवाओं में नशीली दवाओं के खतरों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई।

उन्होंने नशीले पदार्थों का पता लगाने वाली किट भी वितरित की और विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकला, मैराथन, नारा लेखन आदि के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए।

उन्होंने नशा तस्करों से प्रभावी तरीकें से निपटने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के वाहनों को भी हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।

इस अवसर पर नशा निवारण की दिशा में विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदमों पर आधारित नशा निवारण बोर्ड की एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।

इस अवसर पर आईआरबी बनगढ़ और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा नशीली दवाओं के दुष्परिणामों पर आधाारित एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई।

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग यूनुस खान ने मुख्यमंत्रे का स्वागत करते हुए कहा कि इस दिवस को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैधा तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पिछले कुछ दिनों में 40 बीघा से अधिक भूमि पर भांग की खेती को नष्ट किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश को देश का नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए विभाग अधिक समन्वय के साथ कार्य करेगा।

शरीर और मन को शांति प्रदान करता है योग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। योगाभ्यास व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। योग शारीरिक और मानसिक अनुशासन को बनाए रखते हुए शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रिज मैदान पर राज्य के आयुष विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2022 के अवसर पर योग क्रियाओं में भाग लेने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीधे प्रसारण के माध्यम से कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्बोधन भी सुना।

जय राम ठाकुर ने कहा कि योग तनाव और चिंता दूर करता है और हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि यह शरीर में लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के साथ ही श्वसन प्रक्रिया और आंतरिक ऊर्जा के स्तर में भी बढ़ोत्तरी करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में योग को बढ़ावा देने का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने सम्बोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को भारत की प्राचीन परम्परा के एक अमूल्य उपहार की संज्ञा देते हुए मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का आह्वान किया था।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, एसजेवीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा, सचिव आयुष राजीव शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन, पुलिस अधीक्षक मोनिका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

न्यायाधीश अमजद एहतेशाम सईद ने प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की

शिमला/शैल। न्यायाधीश अमजद एहतेशाम सईद ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़ा।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने शपथ पत्र पर राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सांसद प्रतिभा सिंह, महाअधिवक्ता अशोक शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

केन्द्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल के लिए दो परियोजनाए स्वीकृति की:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल के लिए 22.29 करोड़ रुपये की दो बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं स्वीकृत कीं: जय राम ठाकुर

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी) ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएससी-सीडीपी) के अन्तर्गत हिमाचल के लिए दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दोनों परियोजनाएं ऊना जिला की घानरी तहसील के जीतपुर बेहरी में तथा सोलन जिला के परवाणू के खादीन में औद्योगिक एस्टेट के उन्नयन के लिए स्वीकृत की गई हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 22.29 करोड़ रुपये है। इसमें से केन्द्र सरकार का अनुदान 15.92 करोड़ रुपये और राज्य का योगदान 6.37 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में विनिर्माण ईकाइयों की दक्षता में वृद्धि होगी।

केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है और भारत की पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से राज्य को सक्रिय सहयोग मिल रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश में एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण की रणनीति अपनाई है। इससे उनकी सेवाओं को अधिक लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी और लागत में कमी के साथ एमएसएमई निर्माताओं के लिए सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा।

हिमाचल को इस योजना के अन्तर्गत चार बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से तीन के लिए अन्तिम स्वीकृति मिल चुकी है। इन परियोजनाओं में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जिसमें सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे कांग्रेस नेता:बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा विगत कुछ दिनों से प्रदेश सरकार के विरूद्ध की जा रही अनर्गल और असंयमित ब्यानबाजी निंदनीय है तथा इससे उनकी विकृत मनोदशा प्रदर्शित होती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे अथाह विकास एवं सरकार की कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं को मुकेश अग्निहोत्री तथा कांग्रेस पार्टी के नेता पचा नहीं पा रहे हैं जिसके कारण इस तरह की अनर्गल ब्यानबाजी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है जिसके चलते वे पूरी तरह से बौखला गए हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष केन्द्रीय नेतृत्व ने भी मुकेश अग्निहोत्री की प्रदेश में स्थिति का आकलन करने के उपरान्त उन्हें पार्टी ने हाशिए पर रखा है।

उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री सठिया गए हैं जिस कारण वह धैर्यहीन होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की स्वीकृति प्रदेशव्यापी है तथा उनकी लोकप्रियता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसे कांग्रेस नेता पचा नहीं पा रहे हैं।

बिक्रम सिंह ने मुकेश अग्निहोत्री को मर्यादा में रहकर और संयमित ब्यानबाजी करने का परामर्श देते हुए कहा कि व्यक्ति का बड़प्पन उसकी भाषा से झलकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना तो दूर मुकेश अग्निहोत्री हरोली से भी चुनाव हार जाएंगे।

एक लीडर बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है।
.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

घातक होगा अग्निपथ पर बढ़ता विरोध

अग्निपथ योजना का विरोध लगातार बढ़ता और उग्र होता जा रहा है। सरकार और उसके समर्थकों का कोई भी तर्क यह युवा सुनने को तैयार नहीं है। सेना की इस चेतावनी कि जिनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होगी उनके लिये यह दरवाजे बंद हो जायेंगे का भी असर नहीं हुआ है। जनसाख्यिकी के अनुसार देश की 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। 55 से ऊपर के 15% और 25 से 55 के बीच 35% हैं। आज जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं वह सब 25 से कम आयु वर्ग के हैं और सेना में निश्चित रूप से स्थाई रोजगार के पात्र यही लोग थे। यह चाहे मैट्रिक, प्लसटू या ग्रेजुएशन करके सेना का रुख करते वहां पर उन्हें 20 – 25 वर्ष का रोजगार मिलने की संभावना थी। जो केवल 4 वर्ष की ही रह गई है। 4 वर्ष बाद जब यह 23 लाख लेकर वापस आएंगे तो फिर बेरोजगारों की कतार में खड़े होंगे। इन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट सैक्टर में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रखने का आश्वासन दे रहा है। लेकिन क्या यही आश्वासन इनसे पहले भूतपूर्व सैनिकों को नहीं दिये गये हैं? क्या कोई भी सरकार यह दावा कर सकती है कि उसने सभी भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दे रखा है शायद नहीं। फिर 25 से 55 वर्ष के बीच भी तो रोजगार है और इसीलिए सभी सरकारों ने सरकारी सेवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से ऊपर कर रखी है। इस व्यवहारिक स्थिति के परिदृश्य में क्या इन युवाओं को कोई भी तर्क सरकार पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्योंकि दूसरा कड़वा सच यह है कि जिन सरकारी अदारो में रोजगार सृजित होता था उन्हें विनिवेश और मौद्रीकरण के नाम पर सरकार प्राइवेट सैक्टर के हवाले कर चुकी है। प्राइवेट सैक्टर हाथ का विकल्प रोबोट लगाकर छंटनी कर रहा है। इस छंटनी का विरोध न हो इसीलिए कोविड काल में लॉकडाउन के दौरान श्रम कानूनों में संशोधन करके हड़ताल का अधिकार समाप्त किया गया। लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उद्योगों में हाथ की जगह मशीनों ने ले ली है। फिर यह सारे तथ्य एक खुली किताब की तरह हर युवा के सामने है। ऐसे में कोई बताये की युवा इस के सामने रोजगार की उम्मीद कहां बची है? आज क्या बीस लाख रूपये से कोई व्यवसाय शुरू किया जा सकता है? क्या आज बीस लाख बैंक में जमा करवा कर इतना ब्याज मिल सकता है जिसके सहारे वह अपने और परिवार के लिए कोई निश्चित योजना बना सकता है। फिर उसे तो भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी हासिल नहीं होगा। ऐसे में जो प्राथमिकताएं उन्हें आश्वासित की जा रही है वही भूतपूर्व सैनिकों को हासिल है। क्या इससे इनमें अपने में ही हितों के टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो जायेगी? इन सारे पक्षों पर एक साथ विचार करते हुए रोजगार के दृष्टिकोण से इस योजना को लाभदायक नहीं माना जा सकता है। रोजगार से हटकर इस योजना का दूसरा पक्ष और भी गंभीर है। इसके माध्यम से सेना में भी प्राइवेट सैक्टर के दखल का रास्ता खोला जा रहा है। इस समय देश में 35 सैनिक स्कूल चल रहे हैं जिनमें से 33 रक्षा मंत्रालय की सोसाइटी द्वारा संचालित हो रहे हैं और दो राज्य सरकारों के संचालन में हैं। लेकिन इस अग्निपथ योजना के साथ जो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे वह निजी क्षेत्र की पार्टनरशिप में खोले जा रहे हैं। इस भागीदारी में कोई भी एनजीओ, सोसाइटी, स्कूल आदि हो सकता है। यह स्कूल पहले से चल रहे स्कूलों से भिन्न होंगे। यह योजना में ही कहा गया है इस कड़ी में वर्ष 2022 – 23 से 21 स्कूल चालू हो जायेंगे। इनकी सूची जारी कर दी गयी है। इनमें अधिकांश स्कूल आर.एस.एस विद्या भारती के माध्यम से चल रहे हैं। स्वभाविक है कि जब एक विचार धारा की संख्या के साथ पार्टनरशिप रक्षा मंत्रालय की सोसाइटी की हो जाएगी तो दूसरी विचारधारा की संख्या के साथ यह भागीदारी कैसे मना की जायेगी। स्वभाविक है कि जो भागीदार स्कूल चलाने में निवेश करेगा उसके भी अपने कुछ नियम और शर्ते रहेगी। ऐसे में विभिन्न विचारधाराओं द्वारा संचालित स्कूलों से यह बच्चे सेना में एक साथ पहुंचेंगे तो एक अलग ही तरह का परिदृश्य खड़ा हो जायेगा। इसलिए सैनिक स्कूलों के संचालन में प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी के प्रयोग से पहले इस पर एक खुली बहस से सर्वसहमति बनायी जानी आवश्यक थी और इसके अभाव में इस पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। ऐसे में जो विरोध उठ खड़ा हुआ है उसके परिदृश्य में इस योजना को वापिस लेना ही हितकर होगा।

समावेशी राष्ट्रवाद का प्रतीक इस्लामिया विवि महिलाओं को बना रहा सशक्तिकरण

गौतम चौधरी

दिल्ली स्थित जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने समावेशी राष्ट्रवाद के आधारभूत संरचना में अपनी भूमिका निभा रहा है। इन दिनों यह विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन गया है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, द्वारा हाल ही में घोषित लोकसेवा प्रतियोगिता के परिणामों का हाल ही में आंकड़े सामने आए हैं। इसे बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के पहले तीनों प्रतियोगी महिलाएं हैं। इस सम्मानित परीक्षा के आधार पर देश के अगले बैच की आईएएस, आईपीएस और अन्य प्रथम श्रेणी के अफसरों की नियुक्ति तय होगी। इन परिणामों को यह बात अनुठी बनाती है कि इस मुश्किल परीक्षाओं को पास करने वालों में से 23 प्रतियोगी नई दिल्ली स्थित ''जामिया मिलिया इस्लामिया'' विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाली आवासीये कोचिंग अकादमी, आरसीए में पढ़ रहे थे। प्रथम स्थान ग्रहण करने वाली श्रुति शर्मा भी जामिया मिलिया की इस अकादमी की छात्रा थी। इस अकादमी से सफल होने वाले अन्य प्रतियोगियों में अरीबा नोमान, मोहम्मद साकिब आलम, वंदना मीना, नाजिश उमर अंसारी, रामटेक सुधाकर, मोहम्मद कमरुद्दीन, तहसीन बानो द्विवेदी, प्रिया मीना तथा राजा रत्नम गोला इत्यादि शामिल हैं। जिन्होंने इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्थान प्राप्त किए।

ये नतीजे जामिया मिलिया इस्लामिया की उस समर्पण भावना की ओर इशारा करता है, जो उसने अपने विद्यार्थियों के लिए किया है। अधिकारी कितने सफल होंगे यह तो उनकी कार्यशैली पर आधारित होगा लेकिन जामिया विवि ने अपने विद्यार्थियों के लिए जो किया वह एक समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद अहम है। इसे एक ईमानदार पहल कहा जाना चाहिए। जहां एक ओर पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है वहीं भारत के अंदर का वास्तविक चित्र जामिया जैसे विवि में साफ – साफ देखने को मिल रहा है। यह विवि अपने निर्माण काल से ही देश के बौद्धिक आधारभूत निर्माण में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहा है। विद्यार्थियों को ईमानदार और देश के प्रति वफादार बनाने की कोशिश में लगा है। जामिलया मिलिया इस्लामिया को एक ''अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय'' का दर्जा प्राप्त है, फिर भी इसकी संस्कृति, इसका ढ़ाचा, यहां के अध्यापक तथा इसका पाठयक्रम इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वे प्रत्येक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को आत्मसात कर लेते हैं। जामिया एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जो अपने छात्रों के लिए समग्र – संस्कृति व सर्वग्राह्य चिंतन को बढ़ावा देता है तथा उन्हें अपने यहां होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों व आयोजनों द्वारा एकजुट करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया छात्रों के लिए सशक्तिकरण व इसको बढ़ावा देने वाले वातावरण के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी वर्तमान उप – कुलपति प्रो. नजमा अख्तर हैं, जो इस पद को प्राप्त करने वाली यहां की पहली महिला है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित होने वाली कुछ लोकप्रिय महिलाओं में नामवर पत्रकार – बरखा दत्त, अरफा खानु शेरवानी तथा अंजना ओम कश्यप आदि हैं। इसके अलावा फिल्म निर्माता व निर्देशक किरण राय, अभिनेत्री मोनी राय तथा मशहूर मनोरंजक – निधि बिष्ट भी शामिल है। यह सूचि बताती है कि जामिया एक ठेठ अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि यह उन सबके लिए, खास तौर पर औरतों के लिए अपने दरवाजे खोलता है, जो यहां की सेवाएं लेने के लिए इच्छुक हैं। यह विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण के अपने प्रयासों के प्रति भी संवेदनशील दिखता है। यह बात विश्वविद्यालय के दाखिला फार्म से भी झलकती है। जिसमें औरतों के लिए अलग से कोटे का प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार का आरक्षण आरसीए में कोचिंग लेने वालों के लिए बनाए गए आवेदन पत्र में भी ऐसा देखने को मिलता है।

जामिया मिलिया इस्लामिया का जन्म असहयोग आन्दोलन के गर्भ से हुआ था। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर अपनी रचनात्मकता व प्रयोगधर्मी शिक्षा के माध्यम से यहां के गैर शैक्षणिक कर्मचारी, विषयों के प्राध्यापक तथा विद्यार्थी ऐसी स्वतंत्रता भूमि तैयार करते हैं, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सार्थक है। अपने इस प्रयास के द्वारा मुसलमानों ने भी यहां स्वयं को अलग – थलग भारतीय न कहलाने के लिए दूसरों को बाध्य किया है, जो एक समावेशी राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज इस संस्था के निर्माताओं का सपना पूरा होता दिख रहा है क्योंकि जामिया उन सभी के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे माहौल को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है, जो अपने सपनो को पूरा करना चाहते हैं और बिना जाति, रंग या लिंग भेद के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं।?

जामिया मिलिया इस्लामिया में सीएए विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित घटी हिंसक घटनाओं का अंधकार भरा अध्याय अब समाप्त हो चुका है। इसके कही निक्षेप भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शैक्षणिक परिसर अध्ययन और अध्यापन का केन्द्र होता है लेकिन कुछ राजनीतिक सोच वाले इसे अपने उपयोग के लिए भी प्रयोग में लाते रहते हैं। किसी राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्ति भी सबसे पहले शैक्षणिक परिसर को ही अपना निशाना बनाती है। यहां भी यह होता है लेकिन जामिया का अनुभवी परिसार अपने अतीत के प्रभाव तथा संस्थापकों की दूरदर्शिता को संजोए हुए भविष्य की प्रयोगधर्मी बुलंद इमारतों को चाकचौबंद करने में लगा हुआ है। यहां से बहती यमुना नदी में बहुत – सा पानी बह चुका है। संघ लोकसेवा आयोग जैसी सबसे कठिन परीक्षाओं में लगातार सकारात्मक परीक्षा परिणामों द्वारा जामिया ने यह साबित कर दिया है कि वह अब आगे बढ़ चुका है और अब उसका ध्यान औरतों व अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना है। इसने यह भी दिखा दिया है कि अपने सकारात्मक प्रयासों के द्वारा, किसी भी कठिनाई से वह न केवल मुठभेड़ कर सकता है अपितु उस जंग को जीतने की भी ताकत रखता है। एक अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते जहां महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है, वहीं कठोर परिश्रम करने वाले व योग्य अल्पसंख्यक लड़के और लड़कियां, इस विश्वविद्यालय में मौजूद ढ़ाचे का इस्तेमाल कर अपने भविष्य को सवार सकते हैं। यह उनके व देश के प्रकाशमयी व उन्नत भविष्य को सुनिश्चित करेगा। जैसा पिछली बातों से सीखा है कि प्रदर्शन करने की संस्कृति सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लाती है।

राज्य में 10 लाख किसान परिवारों को 1931.63 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार भी किसानों की आय में वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है।

पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की खेती से संबंधित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और उचित फसल स्वास्थ्य और अधिकतम उपज सुनिश्चित करने, विभिन्न आदानों की खरीद, आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीक से लैस करने की परिकल्पना की गई है। योजना के अन्तर्गत पात्र किसान लाभार्थियों को वार्षिक 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ, तीन समान किश्तों में दो-दो हजार रुपये के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

राज्य के किसानों को सशक्त करते हुए पीएम किसान योजना किसानों के छोटे-छोटे खर्चो पूर्ति करने में भी उपयोगी साबित हो रही है और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद और उपकरण खरीदने में सक्षम बना रही है। हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में पीएम किसान योजना के सफल क्रियान्वयन से अब तक लगभग 10 लाख (9 लाख 83 हजार 279) किसान परिवारों को 1931.63 करोड़ रुपये की राशि 11 किश्तों में प्रदान की गई है।

अब तक, जिला बिलासपुर के 59,607 किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 116.75 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जिला चंबा के 70201 किसानों को 142.08 करोड़ रुपये, जिला हमीरपुर के 59699 किसानों को 120. 98 करोड़ रुपये, जिला कांगड़ा के 215069 किसानों को 427.37 करोड़ रुपये, कुल्लू जिले के 68143 किसानों को 140.66 करोड़ रुपये और जिला मंडी के 170136 किसानों को 331.09 करोड़ का भुगतान किया गया है। जबकि जिला शिमला में 93315 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 186.45 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। सिरमौर जिले के 73381 किसानों को 127.37 करोड़ रुपये, सोलन जिले के 68339 किसानों को 137.85 करोड़ रुपये और जिला ऊना के 91325 किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 174.36 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

राज्य के जनजातीय जिलों के किसान भी पीएम किसान योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए है। योजना के कार्यान्वयन से किन्नौर जिले के 10966 किसानों को लगभग 20.72 करोड़ रुपये की राशि और जिला लाहौल स्पीति के 3098 किसानों को लगभग 5.91 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

कोविड महामारी के दौरान भी पीएम किसान योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 11.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और इसी अवधि के दौरान 93246 किसानों ने अपना पंजीकरण भी करवाया।

योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए पीएम किसान पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर और पीएम किसान मोबाइल ऐप भी आरम्भ की गई है। लाभार्थियों को निधि के लेनदेन की निगरानी के लिए पीएम किसान पोर्टल बनाया गया है।

नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुनिया के सभी देशों ने अपनाया योग:अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला। केंद्रीय युवा मामले और खेल व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि योग भारत के प्राचीन इतिहास और परंपराओं का एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि यह मन और शरीर की एकता का प्रतीक है तथा विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य व स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। हमीरपुर जिले में टिहरा सुजानपुर के कटोच पैलेस में एक सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने तथा स्वस्थ तन व मन के निर्माण के लिए युवाओं और विभिन्न वर्गो के लोगों से 365 दिनों तक योग को अपनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार का निर्माण करते हैं जो बदले में स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और अंततः यही बात स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारत की प्राचीन पद्धति योग का महत्व समझाया और दुनिया से इसे अपनाने की अपील की। उनके आहवान पर दुनिया के सभी देशों ने इसे अपनाया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया। भारत के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जीवनशैली बदलने और चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो अंततः हम सभी को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगी। मंत्री ने युवा प्रतिभागियों को अपनी योग सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को कहा ताकि अन्य लोगों को भी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि योग के साथ-साथ भारत शतरंज का भी जन्मदाता रहा है तथा इस वर्ष चौस ओलंपियाड की मेजबानी भी भारत ही कर रहा है। 28 जुलाई से आरंभ होने वाली चौस ओलंपियाड में लगभग 188 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार चैस ओलंपियाड टॉर्च रिले की शुरुआत की गई है और भविष्य में भी हर चैस ओलंपियाड के लिए इस टॉर्च रिले की शुरुआत भारत से ही की जाएगी।

ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के टिहरा सुजानपुर स्थित कटोच पैलेस में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। राजिंदर गर्ग, विधायक घुमारवीं, मीना ठाकुर, ग्राम प्रधान और सदस्य सुजानपुर टिहरा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में मंत्री के साथ मौजूद थे।

इस अवसर पर, मंत्री ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिमला द्वारा लगाई गई 'सेवा-सुशासन-गरीब कल्याण' विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के सभी विकास कार्यक्रमों और प्रयासों को दर्शाया गया है। अपर महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, राजिन्दर चौधरी ने अनुराग ठाकुर को योग पर आधारित पुस्तकों का एक सेट भी भेंट किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित इन चित्रात्मक पुस्तकों में योगासनों को समझाने के लिए कुछ लेखों के साथ चित्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न योगासनों की व्याख्या की गई है।

प्रधानमंत्री ने भी मैसूर पैलेस ग्राउंड से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 समारोह का नेतृत्व किया जिसमें योग द्वारा उत्साहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया व योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया गया जिसमें उन्होंने युवाओं और सभी आयु वर्ग के लोगों से स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा के साथ स्वस्थ जीवन के लिए योग के अमूल्य उपहार को अपनाने का आहवान किया। हिमाचल प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री के संदेश के सीधे प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन स्थापित की गई थी।

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांगड़ा जिले में स्थित कांगड़ा किले से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंडी जिले की पराशर झील से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इसी तरह, केंद्रीय खेल और गृह राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक ने हिमाचल प्रदेश में लेह-मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग से समारोह का नेतृत्व किया। इन चारों स्थानों को देश के 75 प्रतिष्ठित और विरासत स्थलों में से चुना गया था।

हिमाचल प्रदेश के इन सभी चार स्थलों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में समाज के सभी वर्गों के सैकड़ों युवाओं और अन्य लोगों, पंचायती राज संस्थानों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मंडलों, समुदाय आधारित नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेंजर्स और रोवर्स, यानि घूमने आए लोगों सहित आम लोगों ने भी भाग लिया। 'आर्ट ऑफ लिविंग' नामित समूह और नेहरू युवा केंद्र संगठन के योग विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों पर सुबह-सुबह योग करने के लिए प्रेरित किया।

अपर महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, चंडीगढ़, राजिंदर चौधरी, उपायुक्त हमीरपुर, देबशवेता बनिक, नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक सैमसन मसीह पत्र सूचना कार्यालय, केन्द्रीय संचार ब्युरो, हमीरपुर जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र संगठन के ओर से मुख्य अधिकारियों के तौर पर योग सत्र में भाग लेने वालों में शामिल थे जिन्होंने सुजानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त व्यवस्था व सुविधा मुहैया कारवाई।

प्रमुख खाद्य तेल ब्रांडों ने कीमतों में 10 से 15 रुपये की कटौती

शिमला। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में वनस्पति, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल और आरबीडी पामोलिन का थोक और खुदरा मूल्य गिरा है। खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान दिखने और आगे भी इसमें और गिरावट आने के साथ ही, भारतीय उपभोक्ता अपने खाद्य तेलों के लिए कम भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति को भी कम करने में मदद मिलेगी।

पांडे ने कहा, 'सभी प्रमुख खाद्य तेल ब्रांडों ने कीमतों में 10-15 रुपये की कटौती की है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निरंतर निगरानी, सभी हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और सरकार के अनेक हस्तक्षेपों के कारण यह संभव हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक, फॉर्च्यून रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का 1 लीटर पैक की एमआरपी 220 रुपये से घटकर 210 रुपये हो गया है। सोयाबीन (फॉर्च्यून) और कच्ची घानी तेल के 1 लीटर पैक की एमआरपी 205 रुपये से घटकर 195 रुपये हो गई है। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने के बाद तेल के मूल्यों में गिरावट आई है।

डीएफपीडी में संयुक्त सचिव पार्थ एस दास ने कहा कि महाराष्ट्र राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और कर्नाटक में चरण-I और चरण-II में क्रमशः 156 और 84 संस्थाओं का अचानक निरीक्षण किया गया। निरीक्षणों का अच्छा प्रभाव पड़ा क्योंकि आकस्मिक निरीक्षण के चरण-II में चूक करने वाली संस्थाओं की संख्या में कमी आई। उन्होंने कहा कि चरण-I में 53 संस्थाओं और चरण-II में जिन 12 संस्थाओं के निरीक्षण किए गए वह केन्द्रीय स्टॉक नियंत्रण आदेश पर चूक कर रही थी। सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि आवश्यक वस्तु कानून, 1955 के तहत कानून में किए गए प्रावधानों के अनुसार दोषी संस्थाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हालांकि, उचित कार्रवाई करते हुए, राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि प्रतिकूल तरीके से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।

खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की अपनी नवीनतम पहल में, सरकार ने शून्य आयात शुल्क और शून्य एआईडीसी पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में 20 एलएमटी कच्चे सोयाबीन तेल और 20 एलएमटी कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी की है। ऐसा खाद्य तेलों की बढ़ती घरेलू कीमतों, घरेलू मांग में औसत वृद्धि और वैश्विक पाम तेल की उपलब्धता में अनिश्चितता/ गिरावट को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल से खाना पकाने के तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, केन्द्र सरकार ने पहले कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था। इन तेलों पर कृषि उपकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। रिफाइंड सोयाबीन तेल और परिष्कृत सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क मौजूदा 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17. 5 प्रतिशत कर दिया गया है और रिफाइंड पाम तेल पर मूल शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के मुफ्त आयात की अवधि 31.12.2022 तक बढ़ा दी है।

इसके अलावा, देश में खाद्य तेलों और तिलहनों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए लगाई गई है। नियंत्रण आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए प्रमुख तिलहन उत्पादक/ उपभोक्ता राज्यों में खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रखे गए खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक का अचानक निरीक्षण करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की केन्द्रीय टीमों को नियुक्त किया गया था।

सरकार द्वारा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क में कटौती और इंडोनेशिया द्वारा निर्यात प्रतिबंध को हटाने के साथ समय पर उठाए गए उपरोक्त सभी हस्तक्षेपों ने खाद्य तेल कंपनियों के लिए खुदरा कीमतों में कटौती करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया। वैश्विक आपूर्ति में सुधार और टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) का संचालन से कच्चे खाद्य तेलों की कीमतों में और कटौती की उम्मीद की जा सकती है। सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को कम करने के हालिया फैसले ने सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने में मदद की है।

उपरोक्त वस्तुओं की कीमत की स्थिति पर दिन-प्रतिदिन बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि उनकी कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए उचित समय पर उपाय किए जा सकें। सचिव (खाद्य) की अध्यक्षता में कृषि-वस्तुओं पर अंतर-मंत्रालयी समिति किसान, उद्योग और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करती है। समिति साप्ताहिक आधार पर मूल्य की स्थिति की समीक्षा करती है, घरेलू उत्पादन, मांग, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा के आधार पर खाद्य तेलों और अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में महत्वपूर्ण उपायों पर विचार करती है।

जरूरत पड़ने पर सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप और उपायों का इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने पर एक संचयी प्रभाव पड़ा है और यह सुनिश्चित किया है कि कीमतें स्थिर रहें और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो।

सचिव ने वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में भी बात की जिसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 से अब तक 71 करोड़ से अधिक कुल पोर्टेबल लेनदेन की जानकारी दी गई। पोर्टेबल लेनदेन के माध्यम से 40 करोड़ से अधिक की सब्सिडी वितरित की गई है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने 79 करोड़ राशन कार्डो को रखने के लिए एक मजबूत केन्द्रीय डेटाबेस बनाया है जिसका उपयोग भारत सरकार जनता के लाभ के लिए भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए कर सकती है। इस डेटाबेस का उपयोग आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना, श्रम मंत्रालय के लिए कार्यान्वयन को गहराई से लागू करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभाग ने 4.74 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटा दिए हैं।

जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर को मानदेय आधार पर रखने की स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरियां सुनिश्चित करेगी।

बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्यभर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर (1146 पैरा पम्प ऑप्रेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर) को मानदेय आधार पर (6 घण्टे प्रतिदिन) काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की, ताकि आबकारी एनडीपीएस और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के अन्तर्गत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नई उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दम्पति को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कम ब्याज दर पर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के रामपुर में राजकीय उच्च विद्यालय सनारसा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के डलहौजी क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय ग्रैंगर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मंगलेरा, जुटराहन और लदेड़ को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के द्रंग क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय देहरीनाल को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाची में वाणिज्य की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रेसी और चाह का डोहरा में विज्ञान (नॉन मेडिकल) की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों को 7 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के शहीद के सम्मान में जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु का नाम शहीद हवलदार तेज़िंन फुनचोक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसु रखने को अपनी स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में राजकीय उच्च विद्यालय लोहारली, किन्नू और भलोण को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बवेहड़ एवं लोअर अन्दोरा (बदाउ) को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ नव स्तरोन्नत स्कूलों को कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिक्करी नेवल में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्यूरी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नारी को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीहरा एवं ककराना को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी-1 को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय करने सहित विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलोह, जहड़ और गागल शिकोर में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ कर विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करते एवं विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रति वर्ष करने, जमा दो कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष करने को स्वीकृति प्रदान की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना की राशि 10000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20000 से 24000 रुपये प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18000 प्रति वर्ष, विभिन्न युद्धों एवं अभियानों के दौरान शहीद/दिव्यांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18000 रुपये प्रति वर्ष करने और आईआरडीपी/बीपीएल छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने तथा इसके तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र में गांव अप्पर गाहर में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक निदेशालय में तकनीकी सहायक (रेडिएशन सेफ्टी) के दो पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टाण्डा में रेडियोग्राफर के चार पदों को सृजित कर अनुबंध आधार भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत अजौली के गांव नरीवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला के रामपुर बुशहर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के नालागढ़ तहसील के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र पंजेहरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिला के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र सुरल और क्रियूनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला सोलन की तहसील रामशहर के डोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हमीरपुर जिला के धनेटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिला की चुराह तहसील के कोहल और देहग्रां में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन और भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत भटनवाली स्थित किशनपुरा में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र के गांव मुंडी एवं भैरघाट में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की।

बैठक में जिला मंडी के ग्राम पंचायत कल्हणी के सराची में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा तीन पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला और अटल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाना में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसरों के 6 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला के लाहडू में पशु चिकित्सालय तथा मण्डी जिले के सेरू में पशु चिकित्सालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के बियार, बड़ाग्रां, मझोग-सुल्तानी, लम्बलू तथा मण्डी जिले के गाड़ा गुसैणी में स्थित पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में स्तरोन्नत कर विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने बाढ़ नियंत्रण उपमण्डल अम्ब को कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे सहित जल शक्ति मंडल अम्ब में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिला के जल शक्ति मण्डल चम्बा के अन्तर्गत साहू में एक नया जल शक्ति उप-मण्डल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला में जल शक्ति मंडल भोरंज के सुचारू संचालन एवं लोगों की सुविधा के लिए इसके पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला के जल शक्ति उप-मण्डल करसोग के अंतर्गत काव में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला सिरमौर के ददाहु तहसील के गांव बेछर का बाग में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के धरतीधार में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में बीटेक कम्पयूटर विज्ञान एवं अभियान्त्रिकी तथा एमटेक नागरिक अभियान्त्रिकी आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के जरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को अनुमति प्रदान की।

बैठक में जिला मंडी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चच्योट में कढ़ाई एवं बैल्डर के नए ट्रेड आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला सोलन के राम शहर तहसील के क्वारण में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में गाड़ा गुशैणी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की उप-तहसील हरचकियां में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने कृषि एवं बागवानी श्रेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्रत्येक को पांच करोड़ रुपये की अनुसंधान निधि उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के 30 पदों (20 पुरूष एवं 10 महिला) को भरने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से विकास को विनियमित करने के लिए सोलंग विशेष क्षेत्र को अटल टनल के साउथ पोर्टल तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला सोलन के नालागढ़ तहसील के ग्राम मौजना बीड प्लासी में मैसर्स आरकेवी स्पिरिट्स प्राइवेट लि. के पक्ष में आशय पत्र को 31 जुलाई, 2023 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सुन्दरनगर तहसील स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र पुराना बाजार को 10 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को सृजित कर भरने को अनुमति प्रदान की गई। इस अस्पताल में पंचकर्मा की सुविधा भी आरम्भ की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय नोहरा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय नोहरा करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के बनीखेत में राजकीय महाविद्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय लुंज में विज्ञान कक्षाएं (मेडिकल, नॉन मेडिकल) आरम्भ करने और सहायक प्राध्यापकों के 9 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विधिक माप विज्ञान में मैनुअल सहायकों के आठ पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला लाहौल स्पीति में नए स्तरोन्नत किए गए विकास खण्ड उदयपुर में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने नगर विकास खण्ड की 9 ग्राम पंचायतों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत कुल्लू विकास खण्ड में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जिला परिषद संवर्ग के तहत कार्यकारी अभियंता का मंडल खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने डॉ.वाई.एस.परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला अमरकोट, कोलरूबाला, ज्वालापुर, सिरमौरी ताल, गुलाबगढ़, खारा, कुनेर, लोजा, कन्देला, बनग्रां, बेहरीवाला और भटनवाली को राजकीय उच्च विद्यालयों तथा राजकीय उच्च विद्यालय डंगरोहाना, कोटरी व्यास, किशनपुरा और खोदरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 68 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला मखनु माजरा, रंधाला, भांगला, बड्डल, रियाम, ननोबाल-2, सलेहरन, गडौण, प्लासी, जाबेदारहार को स्तरोन्नत कर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैहलीधार और थाच कुठेड़ को स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय तरांगला,

शेष पृष्ठ 7 पर.....

जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर को मानदेय आधार पर रखने

.....पृष्ठ 6 का शेष

कुमारहट्टी, रामपुर पसवालन, धाना तथा सुन्ना को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने और राजकीय उच्च विद्यालय शेरन, जगजीत नगर, मसतानपुरा, साइचरोग, पुरला, गुनाहा, पल्ली, नंगल, नवांग्रां तथा हमीरपुर जिला के राजकीय उच्च विद्यालय पैरवीं को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 78 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानपुरा देवरा, निहालगढ़ और अजौली में विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों टोका नांगला, पुरूवाला, जमनीवाला, किल्लौर और तिम्बी में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में राजकीय माध्यमिक पाठशाला मझार और सिधारी को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और राजकीय उच्च पाठशाला हेलान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से 1000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के पशु औषधालय भंजाल, जोह, घनारी, ठठल और चाक सराई तथा सिरमौर जिला के पशु औषधालय पुरूवाला और शिवपुर, कांगड़ा जिला के पशु औषधालय कुठारना, टटवाणी और सनूहं को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने तथा इन संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के भनेड़ा में नया पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के कुलाल में नया पशु औषधालय, ऊना जिला के हरोट, चराड़ा, बलखालसा और बोहरू तथा मण्डी जिला के बसूट में नए पशु औषधालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के पंजेड़ा में नया पशु अस्पताल खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के सुघ भटोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के रोहाड़ीधार, डीम और डुग्गा में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के साम्बा और सैण्डू में नए स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत हटवास तथा मण्डी जिला की छतरी उप-तहसील के बैठवां गांव में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के खरोठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालीचौकी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाची में बिस्तर क्षमता बढ़ाकर 10 बिस्तर करने और इण्डोर सुविधाएं शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लम्बलू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के पल्यूहण, ककियां और कैला में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत सिराज के दीमन चाहड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत बडारण और कोटला चिल्लियां में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला में 15 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल बंगाणा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थानाकलां में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के लबाणा-डेरा, टाप्पर, चित्रकूट और नड्डल में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़ को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दौलतपुर चौक को 50 बिस्तर क्षमता के सीएचसी में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लपयाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र खुनाची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के कोटिनांबा, सेरी, रानोन, मैहलों और गागुड़ी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के कटवाणू, धबेहर और सुधरनी में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के ईएसआई अस्पताल परवाणू में डॉक्टरों के 6 पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुंडियां को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की सुंदरनगर तहसील के बीणा में नया स्वास्थ्य उप-केन्द्र और चंबा जिला के गांव भदेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामरौ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के दियार में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और सोलन जिला के स्वास्थ्य उप-केंद्र मानपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के बहली कोटी और हलाहा, कुल्लू जिला के करसाई और मंडी जिला के बंदली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के कटौला में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) करसोग में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल व प्लम्बर के नये ट्रेड आरंभ करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटली में प्लम्बर, टेक्निशियन मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स के नये ट्रेड आरम्भ करने का भी निर्णय लिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

संगरूर की हार केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को पहला झटका

- हिमाचल में भी दिल्ली मॉडल सफल नहीं हो सकता
- दिल्ली मॉडल को मुफ्ती की घोषणाओं से मुक्त होना होगा
- आप का प्रादेशिक नेतृत्व अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य के पाठों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है

शिमला/शैल। क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब के संगरूर में हार केजरीवाल के बहुप्रचारित दिल्ली मॉडल को झटका है? क्या यह मॉडल जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है? इसलिए चार माह बाद ही पंजाब की जनता ने इसे नकार दिया? क्या पंजाब की इस हार का असर अन्य राज्यों में भी पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित करेगा? क्या हिमाचल में इसका तुरन्त प्रभाव पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो इस हार के बाद उठ खड़े हुये हैं। क्योंकि पंजाब में चार माह पहले ही पार्टी ने 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी थी। दिल्ली मॉडल के नाम पर पंजाब की जनता ने अन्य दलों को ऐसी हार दी थी की प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरेन्द्र जैसे नेता हार गये। लेकिन आज उसी पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उन्ही के बूथ पर हार मिलना और केवल 45% मतदान होना ऐसा सच है जिसने पार्टी की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। पंजाब की जीत के सहारे ही हिमाचल में पार्टी कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने का दावा करने लगी थी। इस समय जनता महंगाई और बेरोजगारी से इस कदर परेशान हो चुकी है कि वह केंद्र से लेकर राज्यों तक वर्तमान सत्ता से निजात पाना चाहती है इसीलिये आप को यह विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन पंजाब की हार ने विकल्प की सारी संभावनाओं पर अब ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं रह गया है। इस परिदृश्य में यह समझना आवश्यक हो जाता है की जिस दिल्ली मॉडल के नाम पर दिल्ली में सरकार चल रही है और दिल्ली का उप चुनाव भी जीत लिया है तो फिर उसी मॉडल के कारण पंजाब में ऐसी हार क्यूं? यहां यह स्मरण रखना आवश्यक है कि दिल्ली की संरचना देश के अन्य राज्यों से भिन्न है। जितना कर राजस्व दिल्ली को मिलता है उतना किसी दूसरे राज्यों को नहीं मिलता। केंद्र शासित राज्य होने के कारण बहुत सारे विभाग केंद्र के पास हैं। दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र नहीं के बराबर है। दिल्ली की नगर निगमों के पास सरकार का आधे से ज्यादा काम है। दिल्ली में कर राजस्व सबसे अधिक होने के कारण शीला दीक्षित के समय तक सरकार के पास सरप्लस राजस्व था। कैग रिपोर्ट के मुताबिक जब केजरीवाल ने सत्ता संभाली थी तब दिल्ली के पास करीब 13000 करोड़ का सरप्लस था। केजरीवाल ने राजस्व को जनता तक पहुंचाने का काम तो किया। लेकिन इसकी सारी सेवाएं जनता को मुफ्त में उपलब्ध करवानी शुरू कर दी। इस मुफ्ती के कारण जो सरप्लस राजस्व विरासत में मिला था वह अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। बल्कि कोविड काल में केंद्र सरकार से 5000 करोड़ की सहायता मांगने की स्थिति आ गयी थी। मुफ्ती योजनाओं को ही दिल्ली मॉडल की संज्ञा दे दी गयी। पंजाब के चुनाव में भी मुफ्ती के सारे दरवाजे खोल दिये गये। हर वर्ग को कुछ न कुछ मुफ्त देने की घोषणाएं कर दी गयी। दिल्ली में बहुत कुछ मुफ्त मिल रहा था इसलिये पंजाब में भी इस पर विश्वास कर लिया गया और सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन सत्ता में आने पर जब पंजाब की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी सामने आयी तब अपने वायदे पूरे करने के लिये केंद्र से 50 हजार करोड़ की मांग कर दी गयी। इस मांग की प्रतिक्रिया के परिदृश्य में ही तो दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रधानमंत्री से बैठक हुई और यह आग्रह किया गया कि यदि मुफ्ती की घोषणाओं पर अंकुश न लगाया गया तो कुछ राज्यों की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जायेगी। यह इशारा आम आदमी पार्टी और पंजाब की ओर ज्यादा था। यही पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में फिर से बदलाव का कारण बन गया। क्योंकि जनता को तो घोषणा की पूर्ति चाहिये थी। जबकि आज देश का कोई भी राज्य कर्ज के बिना कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं रह गया है। मुफ्ती के वायदे पूरे न हो पाने के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाये गये कदमों का भी जनता पर कोई प्रभाव नहीं हो सका। बल्कि इस हार के बाद यह बहुत आवश्यक हो गया है कि केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को केंद्र और राज्यों की जमीनी आर्थिक स्थिति के आईने में रखकर एक व्यापक बहस कर ली जाये। क्योंकि जब जनता को हकीकत से दो-चार होना पड़ता है तो न केवल उसके भ्रम टूट जाते हैं बल्कि उसका विश्वास भी टूट जाता है। आज पंजाब की हार का असर हिमाचल में भी पार्टी के गठन पर पड़ेगा यह तय है। क्योंकि हिमाचल की जनता को प्रभावित करने के लिये केजरीवाल हर बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपने साथ लेकर आये हैं। परंतु अब जब मान अपने बूथ पर ही हार गये हैं तो हिमाचल की जनता इससे प्रभावित नहीं हो पायेगी। फिर हिमाचल की आप इकाई अभी तक केंद्रीय नेताओं द्वारा पढ़ाये शिक्षा और स्वास्थ्य के पाठ से आगे नहीं बढ़ पाये हैं। फिर यह भी नहीं बताया गया कि इन क्षेत्रों को सुधारने के लिये कौन से व्यवहारिक कदम उठाये जायेंगे। ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि जब तक स्थानीय नेतृत्व की अपनी विश्वसनीयता प्रदेश की जनता में नहीं बन पायेगी तब तक पार्टी का आगे बढ़ पाना बहुत ज्यादा संभव नहीं होगा। संयोगवश प्रादेशिक नेतृत्व में से अभी तक किसी पर भी यह विश्वास नहीं बन पाया है कि उसके पास प्रदेश का विस्तृत अध्ययन हो जो पूरी प्रमाणिकता के साथ कांग्रेस और भाजपा को एक साथ चुनौती देने की क्षमता रखता हो। हिमाचल को दिल्ली के मॉडल से चलाने के प्रयास सफल नहीं हो सकते। यह प्रदेश नेतृत्व को अब समझ आ जाना चाहिये।

पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला क्यों नहीं गया सी.बी.आई.में

- पेपर सैटिंग कमेटी और प्रिंटिंग कमेटी को भेजी गयी अलग-अलग प्रश्नवाली क्या है?
- भर्ती बोर्ड के चेयरमैन आई.जी. जे.पी. सिंह को अलग से प्रश्नावली क्यों भेजी गयी?
- क्या इनके जवाबों से एस.आई.टी. संतुष्ट है?
- प्रिंटिंग प्रैस के चयन की प्रक्रिया क्या रही?

शिमला/शैल। पुलिस भर्ती में पेपर लीक होने और उसके पांच से आठ लाख तक में बिकने के प्रकरण से प्रदेश तथा सरकार की प्रतिष्ठा पर जो दाग लगे हैं वह शायद कभी भी नहीं धुल पायेंगे। क्योंकि जैसे ही यह मामला उजागर हुआ तभी सारा विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच करवाये जाने के ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गये। पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा न जता कर सीबीआई जांच की मांग की गयी। प्रदेश उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका पहुंच गयी। पूर्व में घटे गुड़िया मामले की तर्ज पर इस मामले के भी सीबीआई में जाने की संभावना बढ़ गयी। यह लगने लगा था कि उच्च न्यायालय ही यह जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश कर देगा। क्योंकि पुलिस के खिलाफ पुलिस की ही विश्वसनीय नहीं होने का तर्क खड़ा हो गया था। पुलिस विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास होने से उनकी अपनी प्रतिष्ठा और निष्पक्षता दाव पर आ गयी थी। इस सब को सामने रखकर उच्च न्यायालय की सुनवाई से पहले ही 17 मई को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। सभी ने घोषणा का स्वागत किया और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा बहाल रह गयी।

लेकिन अब 27 जून को जब डी.जी.पी. संजय कुण्डू ने यह घोषणा कर दी कि एक सप्ताह के भीतर इस जांच का चालान अदालत में पेश कर दिया जायेगा और जांच की कुछ तफसील भी पत्रकारों के साथ सांझा कर ली तो वह सारे सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं जो पहले दिन से ही उछल गये थे। फिर कुण्डू ने सारे मामले में संबद्ध पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की संभावना से इन्कार नहीं किया है। अब तक मामले में 171 लोग लोगों की गिरफ्तारी का तथ्य तो समझा कर लिया गया लेकिन यह कहीं सामने नहीं आया कि पुलिस के कितने लोगों से पूछताछ की गयी है। यह भी नहीं बताया गया कि एस.आई.टी. ने पेपर सैटिंग कमेटी और प्रिंटिंग कमेटी को जो अलग-अलग प्रश्नावलियां भेजी थी उनका क्या जवाब आया? क्या उस जवाब से एस.आई.टी. संतुष्ट है? पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन आई.जी. जे.पी. सिंह को अलग से प्रश्न भेजे गये थे उनका क्या जवाब आया है? 2021 में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन मंगवाने का फैसला हुआ था। ए.डी.जी.पी. आर्मड पुलिस, आई.जी. रेंज, वैलफेयर और प्रशासन तथा डी.आई.जी. रेंज तक को बोर्ड में रखा गया था। लेकिन बाद में इस फैसले को किस तरह पर बदला गया यह आज तक सामने नहीं आ पाया है। यह सवाल भी अपनी जगह खड़ा है की पेपरों की प्रिंटिंग हिमाचल सरकार की प्रेस से न करवा कर बाहर से यह प्रिंटिंग करवाने का फैसला किस स्तर पर और क्यों लिया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी ओर शायद जांच में कोई ध्यान नहीं गया है। 2006 के पी.एम.टी. पेपर मामले के अभियुक्त रहे मंडी ट्रक यूनियन के अध्यक्ष रहे मनोज कुमार कि अब इस मामले में भी संलिप्तता का खुलासा करके अपरोक्ष में यह तो कह दिया गया कि पेपर लीक तो बहुत पहले से होती आ रही है। यह तो बता दिया गया कि 10 राज्यों में यह गिरोह सक्रिय है। लेकिन इस सब से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस के अपने ही अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस की ही जांच की इससे विश्वसनीयता कैसे बन जाती है?